Regarding need to fill up vacant government posts under Union and Uttar Pradesh Governments ? laid

श्रीमती संगीता आजाद **(**लालगंज**):** भारत में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) ओ.बी.सी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बीच बेरोजगारी का मुद्दा एक गहरी चिंता का विषय है और इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एससी और एसटी (एसटी) ओ.बी.सी एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के समुदायों के बीच बेरोजगारी की लगातार उच्च दरें एक समावेशी विकास के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हैं जिसे हम अब हल करना चाहते हैं।अगर हम पूर्व में देखें तो उत्तर-प्रदेश में 2007-2012 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लाखों रिक्त सरकारी पदों पर नियुक्तियों का आयोजन किया था ताकि सभी को एक न्यायपूर्ण एवं सम्मानित जीवन जीने का मौका मिल सके। इसलिए, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि केंद्र सरकार और उत्तर-प्रदेश सरकार में एससी एसटी ओबीसी एवं EWS के लिये 2022 -2023 तक कितने स्थायी रोज़गार मिले हैं, कितने पद रिक्त हैं, और अब तक कितने रोज़गार के लिये विज्ञापन निकाले गए हैं, और सरकार इसमें क्यों देरी कर रही है क्योंकि अन्य राज्यों में सरकारी रिक्त पदों को तत्परता से भरा जा रहा है, किन्तु उत्तर-प्रदेश में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अतः मेरी जानकारी में केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में करोडो पद रिक्त हैं, जिन्हें विशेष-अभियान चलाकर नौजवानों को स्थायी रोजगार प्रदान करने का कष्ट करे।